1	2	3	4	5
				dence. Hence it is necessary that special environmental courts or Special Judges may be entrusted with the Jurisdiction for such cases.
14.	Meghalaya	NIL	NIL	NIL
15.	Orissa	NIL	NIL	NIL
16.	Pondicherry	NA	NIL	NIL
17.	Punjab	NA	One	NA
18.	Rajasthan	NA	31 cases	For speedy disposal of pending cases the State Pollution Control Board has requested the State Govt to create a special court, only for this purpose, at Jaipur.
19.	Tamil Nadu	NA	7	Hearings are promptly attended to by the Board's officials for the early disposal of cases.
20.	Tripura	NIL	NIL	Does not arise.
21.	Uttar Pradesh	NA	58	Special Court for the speedy trial of the pollution cases has already been established in this state and further, applications have already been moved before the Hon'ble High Court to expedite disposal.
22.	West Bengal	NA	NIL	NIL

Grants of Pattas to the Tribals in Andhra Pradesh

1134. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the status of grant of pattas or land rights to the tribals of Sunnal Gandi Village in Polararam Mandal in West Godavari district in Andhra Pradesh;

(b) whether it is a fact that delay is being deliberately extended;

(c) whether any effort has been made by Government and the Regional Chief Conservator of Forest, Bangalore to complete the Sunnal Gandi issue; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (c) Government of Andhra Pradesh had sent a case for regularisation of forest land occupied by the tribals of Sunnal Gandi village on 31st January, 1997. The Central Government sought certain clarification from the State Government regarding the survey of land occupied by the tribals. State Government has sent the clarification on 21.9.97 and now the case of regularisation is under process in the Central Government.

(d) Does not arise.

Improvement of Papikonda Sanctuary in Andhra Pradesh

1135. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether a specific representation has been received by Government to improve the Papikonda sanctuary in West Godavari district of Andhra Pradesh;

(b) the details of the representation and the organisation which represented this matter;

(c) the action proposed by Government to examine this request;

(d) the details thereof;

(e) whether an officer will be sent to assess this long pending demand; and

(f) if not reasons for such a neglect?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. A representation was received from Dr. P. Pullarao of West Godavari Distt. of Andhra Pradesh, where in certain issue with regard to the Papikonda wildlife sanctuary were raised and some suggestions for its improvement were made.

(c) to (e) The Chief Wildlife Warden of Andhra Pradesh has been asked to look into the matter and get in touch with Dr. P. Pullarao to find out solutions to the problems of the Papikonda Sanctuary.

(f) Does not arise.

गंगा कार्य-योजना

1136. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा की सफाई के लिए गंगा कार्य-योजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने उपनगरों का मल-जल तथा कितने कारखानों का कचरा गंगा में गिरने से रोका जा चुका है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भावी योजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) गंगा कार्य योजना पर कुल स्वीकृत लागत 462.04 करोड़ रुपये में से 447.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। प्रदूषण निवारण की सीवेज का अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन, सीवेज उपचार संयंत्र, शवदाहगृह, अल्प लागत स्वच्छता, नदी तटाग्र विकास आदि जैसी विभिन्न श्रेणी की स्वीकृत 261 स्कीमों में से 251 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं (विवरण-I) (नीचे देखिए) शेष स्कीमों का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में श्रेणी- I के 25 शहरों के कुल 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन और उपचार का लक्ष्य रखा गया था इसमें से 683 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज के उपचार के लिए क्षमता चालू की गई थी। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए 68 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों का अभिनिर्धारण किया गया था। इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति के अनुसार 45 यूनिटों में बहिस्राव उपचार संयंत्र है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और शेष 23 यूनिटों को बन्द कर दिया गया है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:—

	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल
(i) घोर प्रदूषणकारी उद्योगों की संख्या	34	5	29	68
(ii) उद्योग जिनमें बहिस्राव उपचार संयंत्र है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे है	20	4	21	45
(iii) बन्द किए गए उद्योग	14	1	8	23

(ग) गंगा कार्य योजना को इसके दूसरे चरण तक बढ़ाया गया है और यह गंगा कार्य योजना चरण II है जिसमें गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती और दामोदर के किनारे स्थित 95 शहर शामिल हैं (विवरण II) विभिन्न प्रदूषण निवारण कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।